International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745
Received: 24-02-2026, Accepted: 25-03-2026, Published: 11-04-2026
Volume 8, Issue 2, 2026, Page No. 23-26

भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तीकरण और नवीन सोच की प्रासंगिकता

दीपक नाथ[1], डॉ. हेमा[2]

[1] शोध छात्र, राजनीतिक विज्ञान विभाग, एस एस जे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा, उत्तराखण्ड, भारत

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, शोध निर्देशिका, विभागाध्यक्ष, राजनीतिक विज्ञान विभाग, एस एस जे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच ने पारम्परिक राजनीतिक परिदृश्य को "डिजिटल लोकतन्त्र" में बदल दिया है, जो शासन, जन–भागीदारी और चुनावी रणनीतियों को मौलिक रूप से पुन: परिभाषित कर रहा है। 2014 से शुरू हुए 'डिजिटल इण्डिया' मिशन ने शासन (ई – गवर्नेस) को आम नागरिक तक पहुँचाया है और 2024–25 तक यह एक जन आनदोलन बन चुका है। इस अध्ययन से हम यह जान पायेंगे की 'डिजिटल इण्डिया' ने तकनीक को सुलभ बनाकर नागरिकों को कैसे सशक्त किया है। अब यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन आन्दोलन है। तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किया जा रहा है, जिसमें (AI) को मानव–केन्द्रित (Human – Centric) बनाने पर जोर है। यह शोध ये बतायेगा कि कैसे डिजिटल इण्डिया ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की डिजिटल खाई को कम किया है और दूरदराज के क्षेत्रो तक कनेक्टिविटी पहुंचाई हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (जैसे UPI, (आधार) ने शासन में पारदर्शिता बढाई हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं सीधे जनता को मिल रही हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। टविटर (X), फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने नेताओं को सीधे मतदाताओं से जाता हैं। 'क्रिएटर्स कॉर्नर' जैसे मंचो ने सोशल मीडिया इन्फलुएंसर्स को राज– नीतिक संचार में महत्वपूर्ण बना दिया है। संक्षेप में, भारतीय राजनीति अब " डिजिटल इण्डिया" के माध्यम से एक स्मार्ट, समावेशी और डेटा–संचालित युग में प्रवेश कर चुकी है, जो सुशासन के लिए, नवीन सोच को अपना रही हैं।

मुख्य शब्द: डिजिटल सशक्तिकरण डिजिटल इंडिया ई–गवर्नेंस जन–भागीदारी सोशल मीडिया

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच ने पारम्परिक शासन को पारदर्शी, समावेशी और तेजतर्रार 'डिजिटल लोकतन्त्र में बदल दिया है। Digital India (1 जुलाई 2015) और UPI जैसी पहलों के माध्यम से, सरकार सीधे नागरिकों से जुड रही है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी और जवाबदेही बढी है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म ने युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर, नीति–निर्माण और जन संवाद में "नवीन सोच" को एक जन आन्दोलन बना दिया है। भारतीय राजनीति में तकनीकी अब केवल सूचना का साधन नहीं, बल्कि शासन की रीढ़ बन गई है। डिजिटल इण्डिया, जन–धन–आधार– मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति ने सेवा वितरण को सीधा और पारदर्शी बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे My Gov. नमो ऐप) ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं को नीति–निर्माण में भागीदारी का मौका दिया हैं। यह संचार और संवाद को सरल बनाकर लोकतन्त्र को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहा हैं। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवाओं (ई–हॉस्पिटल, ई–लॉकर) के कारण शासन में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर अकुंश लगा है। डिजिटल इण्डिया ग्रामीण और शहरी अन्तर को कम कर रहा है। यह वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता (PMGDISHA) के माध्यम से दूरदराज के नागरिकों को सशक्त बना रहा है। सोशल मीडिया ने वैकल्पिक राजनीतिक संचार को जगह दी है, जिससे जनमत को प्रभावित करना और जन– समस्याओं को उठाना आसान हो गया है। डिजिटल सशक्तिकरण ने भारतीय राजनीति को एक नया "न्यू इंडिया" दृष्टिकोण दिया है, जो तकनीक आधारित, पारदर्शी और समावेशी शासन की ओर अग्रसर हैं।

अध्ययन के उद्देश्य: भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच (डिजिटल इण्डिया पहल, सोशल मीडिया, और ई–गवर्नेस) का अध्ययन अन्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के लोकतन्त्र की कार्यप्रणाली को मौलिक रूप से बदल रहा है।

- **शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही:** (Transparency & Accountability डिजिटल इण्डिया का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे सरकारी सेवाएँ (जैसे–DBT, आधार, UPI) डिजिटल होकर भ्रष्टाचार मुक्त हो, और शासन से सुशासन की ओर कैसे बढ़ा जाए। डिजिलॉकर और ई– हॉस्पिटल जैसी सेवाओं का उपयोग कर सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना ।

- **समावेशी लोकतन्त्र और नागरिक भागीदारी:** (Inclusive Democracy & citizen Participation) यह अध्ययन करना कि कैसे सोशल मीडिया फेसबुक, टविटर, व्हाट्सएप और मंच (My gov) नागरिकों को सीधे सरकार से संवाद करने और निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर दे रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल साक्षरता की खाई को समझना और यह देखना कि कैसे ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल साक्षरता (PMGDISHA) पहुँच रही हैं।

- **चुनावी राजनीति और जनमत का अध्ययन एवम् नीतिगत और सामाजिक प्रभाव:** (Electoral Politics & Public Opinion Policy & social impact यह अध्ययन करना है, कि कैसे सरकार डेटा का उपयोग करके अधिक प्रभावी नीतियां बना रही हैं, एवम् यह जांचना कि कैसे डिजिटल टूल (जैसे– e–NAM) किसानों और वंचित वर्गों को सशक्त बना रहे हैं और उनके लिए अवसर बढ़ा रहे हैं।' एवम् कैसे राजनीतिक दल पारम्परिक माध्यमों को छोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं (विशेषकर युवाओं) से जुड़ रहे हैं, एआई (AI). डेटा एनालिटिक्स और सूक्ष्म –

लक्ष्यीकरण (Targeted Advertising) का चुनावी परिणामों पर प्रभाव का अध्ययन करना।"

- **चुनौतियाँ और सुरक्षा:** (Challenges and Security) साइबर सुरक्षा के अन्तर्गत डिजिटल युग में चुनावी अखण्डता के लिए साइबर खतरों और डीपफेक (DeepFakes) के प्रभाव का अध्ययन करना एवम् सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली फर्जी खबरों का राजनीतिक माहोल पर क्या असर पड़ रहा है, इसका विश्लेषण करना ।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है, कि डिजिटल तकनीकी भारतीय लोकतन्त्र को अधिक सहभागी, पारदर्शी और कुशल कैसे बना रही है, साथ ही साथ यह भी देखना है कि इस डिजिटल क्रान्ति से जुडी चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए।.

परिकल्पना (hypothesis) :– भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच (Digital Empowerment and New Thinking) एक युगांतकारी बदलाव है, जो डिजिटल इण्डिया शुरुआत (1 जुलाई 2015) की परिकल्पना से प्रेरित है। यह नया भारत (New bharat) बनाने के लिए शासन को पारदर्शी, समावेशी और सीधे नागरिकों से जोड़ने की एक प्रक्रिया हैं।

- **डिजिटल सशक्तिकरण:** नागरिकों को केन्द्र में लाना : (citizen Centric Governance)
- प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच
- पारदर्शिता और जबावदेही'
- डिजिटल साक्षरता ।

- **नवीन सोच:** राजनीति में बदलाव: (Paradigm shift in politics)
- सीधा संवाद (Direct communication)
- डेटा–आधारित निर्णय (Data–Driven politics)
- चुनावी प्रक्रिया में सुधार

- **भविष्य की परिकल्पना:** विकसित भारत (Viksit Bharat)
- युवाओं की भागीदारी (My Gove my Bharat)
- एआई और उन्नत तकनीक
- डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty)

भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण अब सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शासन का 'चरित्र' बन गया है। यह" डिजिटल – प्रथम" (Digital–First) दृष्टिकोण 2047 तक विकसित भारत की ओर बढने में एक प्रमुख स्तम्भ है।

अनुसंधान विधि

भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच का अध्ययन करने के लिए एक बहुआयामी और आधुनिक अनुसंधान विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह क्षेत्र गतिशील है और डेटा तेजी से बदलता है।

- डिजिटल राजनीति में मात्रात्मक (Quantitative) और (गुणात्मक (Qualitative) दोनों पहलू शामिल हैं। यह डिजिटल रुझानों के साथ–साथ उनके पीछे के सामाजिक–मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने में भी मदद करता है।

- वर्णनात्मक (डिजिटल उपकरण फेसबुक, ट्वीटर , व्हाट्सएप) कैसे उपयोग किए जा रहे हैं एवम बिश्लेषात्मक चुनावी परिणाम लोकमत को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।

- डेटा संग्रह के अन्तर्गत ट्वीटर (X), फेसबुक, इंस्टाग्राम पर राजनीतिक दलों और नेताओं के अकाउंटस, रीच, लाइक, कमेट और शेयर का विश्लेषण करना।

- युवा मतदाताओं (Gen Z) और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच –डिजिटल मीडिया के उपयोग और राजनीतिक विचारों पर सर्वेक्षण राजनीतिक रणनीतिकारों, आईटी सेल के सदस्यों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और डिजिटल मार्केटिंग पेशेवरों के साक्षात्कार

- डिजिटल उपकरणों के माध्यम से राजनीतिक जानकारी प्राप्त करने 'वाले समूहों के साथ चर्चा"

भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण के अध्ययन की अनुसंधान विधि को केवल सर्वेक्षण तक सीमित न रहकर डिजिटल एथ्नोग्राफी (Digital Ethnography और बिग डेटा एनालिसिस की ओर बढना चाहिए। यह डिजिटल इण्डिया के माध्यम से हाशिए पर पडे लोगों के सशक्तिकरण और डिजिटल लोकलुभावन (Digital Populism) के बीच के सन्चलन को समझने में मदद करेगा ।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा"

डिजिटल सशक्तिकरण और राजनीतिक सहभागिता:

- **सूचना तक पहुंच:** डिजिटल टूल्स (फेसबुक, ट्वीटर /x, यूटूब, व्हाट्सएप) ने राजनीतिक सूचनाओं को जनता के लिए अधिक सुलब बना दिया हैं। अब नागरिक बिशेष रूप से युवा, सरकार की नीतियों, वादों और उम्मीदवारों के प्रदर्शन को सीधे ट्रैक कर सकते हैं।

- **समावेशी विकास:** सरकारी पहले जैसे 'भारतनेट' और 'प्रधानमत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से साक्षर और सशक्त बना रही हैं, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल हो रहे हैं।

- **महिलाएँ और पंचायत:** ई–गवर्नेस के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व में वृद्धि हुई है। जिससे वे स्थानीय शासन में सक्रिय योगदान दे रही है।

- **'डेटा संचालित प्रचार :** (Data & Driven Compaigns).

2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में डिजिटल मीडिया ने पारम्परिक रैलियों की जगह / पूरक के रूप में सोशल मीडिया को स्थापित किया है। राजनीतिक दल (विशेषकर भापजा) लक्षित मतदाता जुडाव (Targeted Votor Engagement) के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर रहे हैं।

- **पारदर्शिता:** डिजिटल प्रौद्योगिकी ने सरकारी सेवाओं (डीबीटी, जन धन योजना, (आधार) के वितरण में पारदर्शिता बढाई हैं।

- **जवाबदेही:** नागरिक अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलन्द कर सकते हैं, जो राज्य संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को जबावदेह ठहराने का एक नया, अनौपचारिक मंच बन गया है।

- **डिजिटल विभाजन:** (Digital Divide) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इन्टरनेट तक पहुँच में एक बडा अन्तर है (ग्रामीण में 24: बनाम शहरों में 66:)

- **गलत सूचना और ध्रुवीकरण:** (Fake News & Polarization) सोशल मीडिया ने फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन (mis information) और नभरत' भरे भाषणों को बढ़ावा दिया है, जो चुनावी अखण्डता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

- **डेटा सुरक्षा:** डिजिटल प्रक्रियाओं के बढ़ने से नागरिकों की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।

साहित्य यह संकेत देता है कि डिजिटल सशक्तिकरण ने भारतीय राजनीति को अधिक सहभागी बना दिया है। हालांकि, इस नवीन सोच को पूरी तरह सफल बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढाने, ग्रामीण–शहरों अन्तर को पाटने और फेक न्यूज के नियमन के लिए एक मजबूत ढाँचे (Regulation) की आवश्यकता है।'

भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक प्रभाव
भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच ने शासन' व्यवस्था और नागरिक भागीदारी में कान्तिकारी बदलाव लाए है। इसके मुख्य सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है।

1. **सुशासन और पारदर्शिता:** (Good Governance Transparency)
- **भ्रष्टाचार में कमी:** डिजिटल लेन–देन और Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँच रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका और भ्रष्टाचार कम हुआ है।

- **जवाबदेही:** UMANG और DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया है, जिससे सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढी है

2. **समावेशी लोकतन्त्र:** (Inclusive Democracy)
- **नागरिक भागीदारी :** सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से आम नागरिक अपनी राय सीधे सरकार तक पहुँचा पा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक संवाद अधिक समावेशी हुआ है।

- **डिजिटल साक्षरता और जुडाव:** Digital India और Bharat Net जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायते ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी है, जिससे ग्रामीण भारत मुख्यधारा की राजनीति और सेवाओं से जुड़ गया है।

3. **नवीन सोच और राजनीतिक अभियान:** [Innovative Thinking & Political Compaigns] :–
- **डेटा – आधारित निर्णय:** राजनीति में अब डेटा एनालिटिक्स और एआई (AI) का उपयोग मतदाताओं की जरूरतों को समझने और सटीक नीतियाँ बनाने के लिए किया जा रहा है।

- **सोशल मीडिया का प्रभाव:** राजनीतिक दल अब मतदाताओं तक पहुँचने के लिए पारम्परिक विज्ञापनों के बजाय डिजिटल प्लेटफार्म और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं, जिससे प्रचार की लागत कम हुई है और पहुँच बढी है।

4. **आर्थिक सशक्तिकरण:** [Economic Empowerment]
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था':** UPI जैसे डिजिटल भुगतान तन्त्र ने न केवल अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि छोटे उद्यमियों और ग्रामीण आबादी को वित्तीय रूप ले सशक्त बनाया है।

- **रोजगार के नए अवसर:** डिजिटल इण्डिया अभियान से लाखों Common Serve Centers (CSCs) खुले हैं, जो ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और सेवा का केन्द्र बन गए हैं।

डिजिटल तकनीक ने सरकार और नागरिकों के बीच के फासले को कम कर दिया है। जिससे शासन में गति स्पष्टता और विश्वास बढ़ा है।

भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नाकारात्मक प्रभाव
भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच (जैसे–AI, सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स) ने जहाँ पारदर्शिता और समावेशी विकास के नए रास्ते खोले हैं, वहीं इससे कई गम्भीर नाकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं, जो 2026 के परिदृश्य में और अधिक जटिल हो गए हैं।

डिजिटल राजनीति के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है
- **दुष्प्रचार और फेक न्यूज:** (Misinformation anal Fake News) सोशल मीडिया (WhatsApp, Telegram) के माध्यम से गलत सूचनाएं और फेक न्यूज तेजी से फैलती हैं, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित होता है और नागरिकों की राय गलत तथ्यों पर बन सकती है।

- **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** (Political Polarization) सोशल मीडिया एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को केवल उनकी पसन्द की सामग्री दिखाते है, जिससे इको चेंबर (Echo chambers) बनते हैं। इससे समाज में ध्रुवीकरण बढता है और विपरीत विचारधाराओं के प्रति असहिस्णुता पैदा होती है।

- **गहरी चिन्ता और दीपफेक:** (Deepfakes and AI Misuse) 2026 तक, एआई–आधारित दीपफेक तकनीक ने नेताओं के नकली बीडियो और वॉयस किल्प बनाकर मतदाताओं को गुमराह करने का खतरा बढा दिया है, जिससे चुनावी सत्यता पर सवाल उठते हैं।

- **डिजिटल विभाजन** (Digital Divide) यद्यपि स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच इन्टरनेट की गति और डिजिटल साक्षरता में बड़ा अन्तर हैं। इससे ग्रामीण या सीमान्त समुदायों की राजनीतिक भागीदारी पर नकारात्मक असर पड़ता है।

- **निजी डेटा का दुरुपयोग और निगरानी:** (Data Piracy and Surveillance) राजनीतिक दलों द्वारा डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी (micro-Targeting) का इस्तेमाल हेरफेर के लिए किया जा सकता है, जो निजता के अधिकार के लिए खतरा है

- **पारम्परिक कार्यकर्ताओं की प्रासंगिकता में कमी:** डिजिटल अभियानों के चलते, जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका कम हो रहीं जिससे पार्टी आलाकमान का सीधा नियंत्रण बढ़ रहा है और स्थानीय मुद्दों को नजरअन्दाज किया जा सकता है।

- **साइबर सुरक्षा खतरे** Cybersecurity Threats) बढ़ते डिजिटल डिजिटलीकरण के साथ, चुनावी बुनियादी ढाँचे पर साइबर हमले और डेटा चोरी का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता खतरे में पड़ सकती है।

- **हेट स्पीच और साइबरबुलिंग:** सोशल मीडिया पर गुमनामी की आड़ में नफरत भरे भाषण (Hate Speech) और ऑनलाईन उत्पीड़न बढ गया है, जिससे स्वस्थ राजनीतिक निर्माण को नुकसान पहुँचता है।

संक्षेप में, डिजिटल शक्ति ने राजनीति को तीव्र और सुलभ तो बनाया है, लेकिन यह लोकतन्त्र के लिए ध्रुवीकरण, दुष्प्रचार, और डेटा सुरक्षा के रूप में बड़ी चुनोतियां भी पेश कर रहा है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण और नवीन सोच ने पारम्परिक लोकतान्त्रिक ढांचे को एक 'डिजिटल लोकतन्त्र' में बदल दिया हैं। 'डिजिटल इण्डिया' कार्यक्रम के 10 वर्षों (2015–2025) ने न केवल शासन को पारदर्शी बनाया है, बल्कि नागरिकों की भागीदारी को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। ई–गवर्नेस जैसे (उमंग ऐप, डिजिलॉकर) और आधार – आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ने भ्रष्टाचार को कम किया है और सरकारी सेवाओं को आम नागरिक के घर तक पहुँचाया हैं। डिजिटल तकनीक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ रही है। 2025 तक 5ळ सेवाओं की पहुँच और 85ः से अधिक परिवारों के पास स्मार्टफोन होने से, राजनीतिक संवाद अब केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा है। सोशल मीडिया (WhatsApp, Instagram, X) के माध्यम से मतदाता सीधे नेताओं से जुड़ रहे हैं। इसने राजनीतिक विमर्श को अधिक सहभागी बना दिया है। अब चुनाव केवल शैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया अभियान और डिजिटल प्रचार अहम हो गए हैं। डेटा एनलिटिक्स और AI का प्रयोग मतदाताओं को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे चुनाव अभियानों का स्वरूप बदल गया है। डिजिटल कौशल (PMGDISHA) और डिजिटल साक्षरता के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। हांलाकि, डिजिटल विभाजन (ग्रामीण–शहरी अन्तर), साइबर सुरक्षा, और फर्जी खबरों (Fake News) का प्रसार बड़ी चुनौतियां हैं। भविष्य में, एक समावेशी और सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्र का निर्माण करना ही भारत की राजनीतिक सफलता की कुंजी हैं। भारतीय राजनीति में डिजिटल सशक्तिकरण समावेशी विकास, शासन में पारदर्शिता और सक्रिय नागरिक भागीदारी का एक नया अध्याय लिख रहा है, जो 'सुगम जीवन' (Ease of Living) की दिशा में एक बड़ा कदम है

सन्दर्भ सूची

1. Digital India & MyGov-in : 9 + वर्ष के डिजिटल सशक्तिकरण का डेटा
2. 2–PIB (प्रेस सूचना ब्यूरो): ग्रामीण डिजिटल विकास (e-NAM, CSCs) की रिपोर्ट .
3. भारत एआई (India-AI): गवर्नेस में AI का एकीकरण
4. BBC News India ! 2024 चुनावों में AI का उपयोग
5. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2015–2025)
6. पाठक, आर. (2020): भारतीय चुनावों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जयपुर: रावत पब्लिकेशन
7. पलट, ए. (2019): भारतीय लोकतन्त्र में जनसंचार और चुनाव, भोपाल: ज्ञानदीप प्रकाशन।
8. लाल, आर. (2023): भारत में चुनाव सुधार और तकनीकी बदलाव दिल्ली: ओम पब्लिकेशन
9. मनजार, ओ. (2026) : फना–ए–हक (Fana-e-Haq) डिजिटल' युग में अधिकारों के क्षरण पर विचार
10. आचार्य, मंगेश (2022): भारतीय राजनीति में युवाओं की भूमिका एक राजनीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन
11. भारत सरकार की पीआईबी (PIB) प्रेस विज्ञप्तियां, डिजिटल इण्डिया पोर्टल, और ई–गवर्नेस की रिपोर्टस
12. एकेडमिक रिपोर्टस : इंटरनेशनल IDEA, EPW और "Digital Democracy in India' (SRJIS)
13. अध्ययन (2024–2025): 2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एआई–संचालित अभियानों पर केन्द्रित शोध (The Hindu] Business standard)
14. दृष्टि I.A.S. (www. drishtisas)
15. ध्येय I.A.S. (www dhyeyaias. com)